

# VII

## लोक ऋण प्रबंधन

कठोर चलनिधि स्थितियों के बावजूद रिजर्व बैंक ने 2012-13 के दौरान सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित किया। सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के भारित औसत प्रतिफल में कमी आई लेकिन भारित औसत परिपक्वता में बढ़ोतरी हुई। हाल के वर्षों में उच्च मुद्रास्फीति के बीच जोखिम से बचना चाहने वाले निवेशकों को बेहतर विकल्प प्रदान करके बचतों को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड जारी किये।

### केन्द्र सरकार के ऋण का प्रबंधन

#### बाजार से ऋण

VII.1 वित्तीय वर्ष 2012-13 में मुद्रास्फीतिकारक दबाव और कठोर चलनिधि स्थिति लगातार बनी रही। सरकार के ऋण प्रबंधन के रूप में रिजर्व बैंक ने दो प्रमुख उद्देश्यों, अर्थात् लागत कम करने और रोलओवर जोखिम के अनुरूप परिपक्वता प्रोफाइल के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित किया। 5,580 बिलियन रुपये का बाजार उधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तथापि, प्राथमिक व्यापारियों पर पिछले वर्ष के 121 बिलियन रुपये की तुलना में 18 बिलियन रुपये की प्रतिभूतियाँ डिवाल्व हुईं। 2012-13 में दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए उगाही गई सकल और निवल राशि पिछले वर्ष की राशि से क्रमशः लगभग 9 प्रतिशत और 7 प्रतिशत अधिक थी (सारणी VII.1)।

### सारणी VII.1: केन्द्र सरकार की सकल और निवल बाजार उधारियां #

(₹ बिलियन)			
मद	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4
निवल उधारियां	3,254 (3,450)	4,364 (3,430)	4,674 (4,790)
सकल उधारियां	4,370 (4,571)	5,100 (4,171)	5,580 (5,696)

# दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए निर्गम

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बजट अनुमान से लिए गए हैं।

VII.2 दिनांकित प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल मुख्यतः दीर्घावधि दिनांकित प्रतिभूतियों के प्रतिफल में कमी आने के कारण 2011-12 के 8.52 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में 8.36 प्रतिशत रह गया। तथापि, सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक पर भारित औसत कूपन दर 31 मार्च 2012 के 7.88 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 7.97 प्रतिशत हो गई (सारणी VII.2)।

### सारणी VII.2: केन्द्र सरकार का बाजार ऋण - एक प्रोफाइल#

(प्रतिफल प्रतिशत में, परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक इश्यू पर वार्डटीएम का अनुक्रम			वर्ष के दौरान इश्यू			बकाया स्टॉक (मार्च के अंत में)	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	प्रतिभूतियों की अवधि	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	7.71-8.42	7.69-8.77	7.77-8.81	7.69	6-30	13.8	10.45	8.23
2009-10	6.09-7.25	6.07-7.77	6.85-8.43	7.23	5-15	11.16	9.82	7.89
2010-11	5.98-8.67	7.17-8.19	7.64-8.63	7.92	5-30	11.62	9.78	7.81
2011-12	8.21-8.49	7.80-10.01	8.25-9.28	8.52	7-30	12.66	9.60	7.88
2012-13	8.82-8.21	7.86-8.76	7.91-8.06	8.36	5-30	13.50	9.67	7.97

#: एमएसएस के तहत जारी निर्गम शामिल नहीं हैं; वार्डटीएम: परिपक्वता प्रतिफल

VII.3 वर्ष के दौरान दीर्घावधि वाली दिनांकित प्रतिभूतियाँ अधिक मात्रा में जारी की गईं जिसके चलते ऋण प्रतिभूतियों की औसत परिपक्वता पिछले वर्ष के 12.66 वर्ष से बढ़कर 2012-13 में 13.50 वर्ष हो गई।

VII.4 बकाया स्टॉक (अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर) की भारत औसत परिपक्वता 31 मार्च 2012 के 9.60 वर्ष से बढ़कर 31 मार्च 2013 को 9.67 वर्ष हो गई (सारणी VII.2)। 2012-13 के दौरान लगभग 31 प्रतिशत बाजार ऋण 10-15 वर्ष की परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए लिया गया जबकि 2011-12 में यह 24 प्रतिशत था (सारणी VII.3)।

VII.5 केंद्रीय बजट 2013-14 के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों के जरिए भारत सरकार की सकल बाजार उधारियाँ 500 बिलियन रुपये के बाईबैंक/स्विचेज को छोड़कर 5,790 बिलियन रुपये (निवल 4,840 बिलियन रुपये) रहने का अनुमान है। दिनांकित प्रतिभूतियों का 2013-14 की पहली छमाही का निर्गम-कैलेंडर भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श करके 18 मार्च 2013 को जारी किया गया। वर्ष की पहली छमाही में 3,490 बिलियन रुपये की राशि उगाहने की योजना है जबकि पिछले वर्ष की इसी छमाही में उगाही गई ऐसी राशि 3,700 बिलियन रुपये थी। सकल रूप में 2,400 बिलियन रुपये का बाजार ऋण (और निवल रूप में 2,272 बिलियन रुपये) उगाहने का कार्य 5 अगस्त 2013 तक पूरा कर लिया गया। दिनांकित प्रतिभूतियों की भारत औसत परिपक्वता पिछले वर्ष की इसी अवधि के 13.62 वर्ष से बढ़कर 14.4 वर्ष हो

गई। प्राथमिक नीलामी के दौरान भारत औसत प्रतिफल पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 8.50 प्रतिशत से कम होकर 7.80 (आईआईबी को छोड़कर) प्रतिशत रह गई।

VII.6 खजाना बिलों की नीलामी के प्रतिफल में जून 2013 को समाप्त तिमाही के मध्य तक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई किन्तु मई 2013 में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की प्रतिक्रिया के बाद इसमें बढ़ोतरी होना शुरू हुई। चलनिधि की उपलब्धता को सख्त बनाने संबंधी उपायों के बाद खजाना बिलों के प्रतिफल में काफी बढ़ोतरी (91-दिवसीय और 364-दिवसीय खजाना बिलों में क्रमशः 273 आधार अंक और 209 आधार अंकों की बढ़ोतरी) हुई।

VII.7 वर्ष 2013-14 के केंद्रीय बजट में ऐसे लिखत की शुरुआत करने का प्रस्ताव था जो बचतों, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गों की बचतों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचा सके। बजट घोषणा को ध्यान में रखते हुए 4 तथा 25 जून 2013 को नीलामी प्रक्रिया के जरिए मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड (आईआईबी) जारी किए। इनसे आशा है कि ये वास्तविक प्रतिफल के लिए बेंचमार्क प्रदान करेंगे। बाद में 2013-14 की दूसरी छमाही में सिर्फ खुदरा निवेशकों के लिए ही मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड जारी किए जाएंगे (बाक्स VII.1)।

#### नकदी प्रबंधन

VII.8 सरकार के पास वर्ष 2012-13 की शुरुआत में 742 बिलियन रुपये का नकद अधिशेष था, किन्तु अपनी व्यय संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकार को शीघ्र ही 12 अप्रैल

#### सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(₹ बिलियन)

अवशिष्ट परिपक्वता	2010-11		2011-12		2012-13	
	उगाही गई राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	उगाही गई राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत	उगाही गई राशि	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्ष से कम	110	2.52	180	3.53	470	8.42
5-9.99 वर्ष	1,520	34.78	2,340	45.88	1,910	34.23
10-14.99 वर्ष	1,640	37.53	1,230	24.12	1,730	31.00
15-19.99 वर्ष	540	12.36	650	12.75	270	4.84
20 वर्ष और उससे अधिक	560	12.81	700	13.73	1,200	21.51
<b>कुल</b>	<b>4,370</b>	<b>100.00</b>	<b>5,100</b>	<b>100.00</b>	<b>5,580</b>	<b>100.00</b>

## बाक्स VII.1

### मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड का निर्गम

ऋण प्रबंधन रणनीति में किफायती और बाधा रहित तरीके से लोक ऋण का प्रबंधन करने के लिए अनेक लिखत होने चाहिए। मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सरकार के बाजार ऋण के लिए एक महत्वपूर्ण लिखत के रूप में सामने आया है (सारणी 1)।

यद्यपि ऋण प्रबंधन रणनीति के अंतर्गत बाजार ऋण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के लिखत जारी किये जा रहे हैं, फिर भी ऐसी रणनीति मुख्यतः नियत दर वाले सांकेतिक बांडों पर निर्भर रही है। मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड का एक प्रकार, पांच वर्षीय पूंजी सूचकांकित बांड (सीआईबी) 29 दिसंबर 1997 को जारी किया गया जिसमें केवल मूलधन के भुगतान को चुकौती के समय मुद्रास्फीति के साथ सूचकांकित किया गया था। परंतु, यह निर्गम अधिक सफल नहीं हुआ क्योंकि यह ब्याज के भुगतान को मुद्रास्फीति के प्रभाव से रक्षित नहीं करता था।

यह सर्वविदित तथ्य है कि बैंकों के लिए एसएलआर रखने की जरूरत और बीमा कंपनियों तथा प्रॉविडेंट फंडों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में कुछ न्यूनतम निवेश की जरूरत के चलते सरकारी प्रतिभूतियों की एक निश्चित मांग है। बाजार ऋण की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए ऋण प्रबंधन रणनीति का

प्रयास लगातार निवेशक आधार बढ़ाना, विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों की निश्चित मांग में कमी आने की संभावना से निपटना, होना चाहिए। इसके लिए पूर्व अनुभवों, बाजार के सहभागियों से प्राप्त फीडबैक और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से मिली सीख के आधार पर मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड का नया स्वरूप तैयार किया गया है जिसमें ब्याज के भुगतान और मूलधन की चुकौती की राशि को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के उपाय किए गए हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- मूलधन को मुद्रास्फीति से सूचकांकित किया जाएगा (सूचकांक अनुपात);
- कूपन का भुगतान सूचकांकित मूलधन पर किया जाएगा;
- चुकौती के समय समायोजित मूलधन अथवा अंकित मूल्य में से जो अधिक हो उस राशि का भुगतान किया जाएगा; और
- मूलधन को सूचकांकित करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाएगा।

रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति सूचकांकित सरकारी स्टॉक के नाम से इस उत्पाद की शुरुआत की और 4 जून 2013 को 10 बिलियन रुपये की पहली नीलामी आयोजित की। सरकारी बाजार उधार कार्यक्रमों की मदद करने के अलावा, इस उत्पाद के अनेक अन्य लाभ भी हैं। मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड की शुरुआत किए जाने से मूल्य स्थिरता के प्रति सार्वजनिक नीति की विश्वनीयता में सुधार हो सकता है। दीर्घावधि के वित्तीयन में हमेशा ही बहुत अधिक मुद्रास्फीति जोखिम रहता है जिसका निराकरण मुद्रास्फीति संबद्ध लिखत के जरिए ऋण लेकर किया जा सका। यह निजी क्षेत्रों और बैंकों को एक बेचमार्क प्रदान करेगा और इससे उन्हें मुद्रास्फीति-संबद्ध लिखत के जरिए दीर्घावधि ऋण लेने में आसानी होगी। इसलिए यह उत्पाद इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यह मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को बेहतर ढंग से जानने में भी मदद करेगा जो मौद्रिक नीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचने के लिए लोगों द्वारा सोने में किया जाने वाले निवेश में कमी आ सकती है और यह देश के भुगतान-संतुलन में मदद कर सकता है।

इसकी खुदरा सहभागिता बढ़ाने देने के लिए गैर-प्रतिस्पर्धात्मक हिस्से को अधिसूचित राशि के 20 प्रतिशत तक निश्चित किया गया है। यदि बीमा कंपनियों, पेन्शन फंडों, प्रॉविडेंट फंडों जैसे संस्थागत निवेशकों के भुगतान मुद्रास्फीति से संबद्ध हों तो इनसे भी मुद्रास्फीति सूचकांकित बांडों की कुछ मांग हो सकती है। बैंक भी इस उत्पाद में अपनी परिपक्वता अवधि के आधार पर निवेश कर सकते हैं क्योंकि वे इसके जरिए दीर्घावधि जमा राशियाँ जुटा सकते हैं।

**सारणी 1: विभिन्न देशों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी देशी बांडों की संरचना**  
(बकाया प्रतिशत के रूप में) (2011 के अंत में)

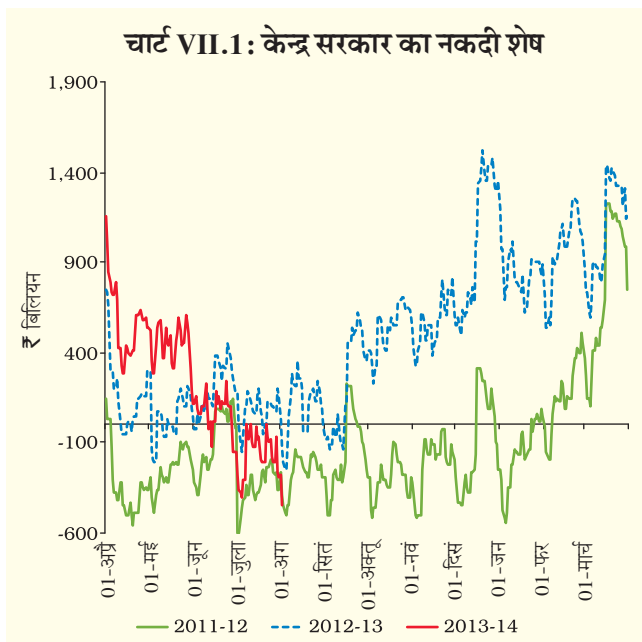
देश	अस्थिर दर	स्थिर दर	मुद्रास्फीति सूचकांकित	विनियम दर से संबद्ध	अन्य
1	2	3	4	5	6
अर्जेंटीना	14.8	0.8	49.2	34.6	0.7
ब्राजील	31.9	37.5	30.0	0.6	0.0
चिली	0.0	19.2	80.8	0.0	0.0
भारत	2.4	97.6	0.0	0.0	0.0
इंडोनेशिया	22.2	77.8	0.0	0.0	0.0
कनाडा	0.0	92.5	7.5	0.0	0.0
दक्षिण अफ्रीका	11.6	70.8	17.6	0.0	0.0
मेक्सिको	41.4	36.6	22.1	0.0	0.0
जर्मनी	10.9	85.8	2.9	0.4	0.0
यूके	0.0	77.6	22.4	0.0	0.0
यूएसए	0.0	91.2	8.8	0.0	0.0

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस)

2012 को अर्थोपाय अग्रिम का सहारा लेना पड़ा (चार्ट VII.1)। उसके बाद भारत सरकार ने 12 बार अर्थोपाय अग्रिमों का सहारा लिया, लेकिन 15 सितंबर 2012 से 31 मार्च 2013 तक उनकी शेषराशि धनात्मक रही। वर्ष के दौरान भारत सरकार ने 40 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिमों का सहारा लिया और ओवरड्राफ्ट नहीं लिया जबकि पिछले वर्ष सरकार ने 263 दिनों के लिए अर्थोपाय अग्रिम और 70 दिनों के लिए ओवरड्राफ्ट लिया था।

VII.9 वित्तीय वर्ष 2012-13 की पहली छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा, पहली तिमाही के लिए 500 बिलियन रुपये और दूसरी तिमाही के लिए 450 बिलियन रुपये निर्धारित की गई थी। वर्ष की दूसरी छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 200 बिलियन रुपये निर्धारित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2013-14 की पहली छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 300 बिलियन रुपये निर्धारित की गई है। चालू वित्तीय वर्ष (2013-14) के दौरान 5 अगस्त

चार्ट VII.1: केन्द्र सरकार का नकदी शेष



2013 तक भारत सरकार ने 27 दिन अर्थोपाय अग्रिम तथा 4 दिन ओवरड्राफ्ट लिया।

### राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

#### बाजार से ऋण

VII.10 राज्य सरकारों के बाजार ऋण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2012-13 के लिए 1,881 बिलियन रुपये का निवल आबंटन किया गया था। 306 बिलियन रुपये की चुकौती को ध्यान रखते हुए जहाँ सकल आबंटन 2,187 बिलियन रुपये रहा, वहीं अनुच्छेद 293(3) के तहत सकल मंजूरीयाँ 1,861 बिलियन रुपये रहीं। 2012-13 में 28 राज्य सरकारों ने 1,773 बिलियन रुपये (निवल 1,467 बिलियन रुपये) की सकल राशि का ऋण लिया जबकि पिछले वर्ष 26 राज्यों ने 1,586 बिलियन रुपये (निवल 1,366 बिलियन रुपये) की सकल राशि का ऋण लिया था (सारणी VII.4)। ओडिशा सरकार ने 2012-13 में बाजार उधार कार्यक्रम में भाग नहीं लिया जबकि 2011-12 में असम, ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने इसमें भाग नहीं लिया था। 2012-13 में 11 राज्यों ने अपनी समस्त मंजूर राशि का ऋण नहीं लिया जबकि 2011-12 में 14 राज्यों ने ऐसा किया था। मार्च 2013 की समाप्ति पर एसडीएल और पावर बांड का बकाया स्टॉक 8,874 बिलियन रुपये रहा (सारणी VII.5)।

सारणी VII.4: राज्यों की बाजार उधारियाँ

(₹ बिलियन)

Item	2011-12	2012-13	2013-14 (5 अगस्त 2013 तक)
1	2	3	4
निवल आबंटन	1,459	1,881	-
अतिरिक्त आबंटन	157	0	0
वर्ष के दौरान परिपक्वताएं	220	306	291.84
सकल आबंटन	1,835	2,187	-
अनुच्छेद 293 (3) के तहत सकल मंजूरीयाँ	1,634	1,861	832.95
वर्ष के दौरान उगाही गई सकल रकम	1,586	1,773	481.31
वर्ष के दौरान उगाही गई निवल रकम	1,366	1,467	189.47
भारत सरकार की मंजूरीयों के आधार पर उगाहा जाने वाला शेष	48	89	351.64
कुल मंजूरीयों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान उगाही गई रकम	97.09	95.22	-
एसडीएल बकाया (अवधि की समाप्ति पर)	7,424	9,291	-

VII.11 भारत औसत प्रतिफल पिछले वर्ष (2011-12) के 8.79 प्रतिशत से बढ़कर 8.84 प्रतिशत (2012-13) हो गया क्योंकि एसडीएल निर्गम का भारत औसत अंतर तदनुसूची भारत सरकार की प्रतिभूति की तुलना में पिछले वर्ष के 44 आधार अंकों से बढ़कर 71 आधार अंक हो गया था।

सारणी VII.5: बकाया राज्य विकास ऋण और पावर बांड की अवशिष्ट परिपक्वता प्रोफाइल (मार्च 2013 की समाप्ति पर)

(₹ बिलियन)

परिपक्वता वर्ष	राज्य विकास ऋण	पावर बांड	कुल
1	2	3	4
2013-14	321	29	350
2014-15	334	29	363
2015-16	352	29	381
2016-17	315	14	329
2017-18	678	0	678
2018-19	1,181	0	1,181
2019-20	1,306	0	1,306
2020-21	1,045	0	1,045
2021-22	1,586	0	1,586
2022-23	1,654	0	1,654
<b>कुल</b>	<b>8,772</b>	<b>101</b>	<b>8,873</b>

**सारणी VII.6: डब्ल्यूएमए/ओडी का उपयोग और राज्य सरकार का निवेश@  
(औसत मासिक बकाया)**

(₹ बिलियन)

माह	विशेष डब्ल्यूएमए			सामान्य डब्ल्यूएमए			ओवरड्राफ्ट			कुल		
	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अप्रैल	10.0	5.0	0.8	7.0	4.0	3.0	9.0	3.0	2.0	26.0	12.0	5.8
मई	6.0	1.0	0.6	1.0	0.3	1.3	0.4	0.0	0.2	7.4	1.4	2.1
जून	2.0	0.6	5.8	3.0	2.0	5.3	0.1	0.2	2.1	5.1	2.8	13.2
जुलाई	1.0	2.0	1.9	1.0	2.0	2.9	0.0	0.8	0.6	2.0	4.8	5.4
अगस्त	2.0	0.6	4.0	3.0	1.0	0.4	0.0	0.3	0.0	5.0	1.9	4.5
सितंबर	1.0	4.0		2.0	4.0		0.1	2.0		3.1	10.0	
अक्टूबर	1.0	5.0		2.0	4.0		0.1	1.0		3.1	10.0	
नवंबर	5.0	5.0		2.0	4.0		0.0	1.0		7.0	10.0	
दिसंबर	3.0	4.0		1.0	4.0		0.1	2.0		4.1	10.0	
जनवरी	3.0	0.6		1.0	1.0		0.0	0.1		4.0	1.7	
फरवरी	0.5	0.1		1.0	3.0		0.0	2.0		1.5	5.1	
मार्च	0.2	0.9		1.0	1.6		0.3	4.9		1.5	0.0	

@ : 5 अगस्त 2013 तक

**नकदी प्रबंधन**

VII.12 संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी सहित राज्यों के लिए समग्र सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 2012-13 के लिए 102 बिलियन रुपये निर्धारित की गयी जो पिछले वर्ष के समान है। सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट की ब्याज दरें रिपो दर से संबद्ध बनी रहीं। 2012-13 में सभी राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट का मासिक औसत उपयोग 2011-12 की तुलना में जुलाई, सितंबर-दिसंबर और फरवरी में अपेक्षाकृत अधिक किया

गया (सारणी VII.6)। 2013-14 (अब तक) के दौरान 5 राज्यों ने ओवरड्राफ्ट का उपयोग किया है (सारणी VII.7)।

VII.13 राज्य सरकारों की अधिशेष में स्थित नकद राशि स्वचालित तरीके से 14-दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों में निवेश कर दी जाती है जिसके लिए वर्तमान में बट्टा दर 5 प्रतिशत निर्धारित है। 14-दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिलों (आईटीबी) में औसत निवेश 2011-12 के 722 बिलियन रुपये से बढ़कर 2012-13 में 849 बिलियन रुपये हो गया (सारणी VII.8)। मध्यवर्ती खजाना बिलों

**सारणी VII.7: राज्यों द्वारा विशेष/सामान्य डब्ल्यूएमए/ओडी का उपयोग करने के दिनों की संख्या@**

राज्य	विशेष डब्ल्यूएमए			सामान्य डब्ल्यूएमए			ओवरड्राफ्ट		
	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	23	13	2	22	12	1	6	5	0
नागालैंड	41	193	76	20	139	56	0	34	35
पंजाब	177	233	74	177	232	74	26	139	37
पश्चिम बंगाल	185	134	38	59	48	15	28	13	9
महाराष्ट्र	0	7	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0	98	12	0	81	8	0	30	8
मिजोरम	15	7	64	1	3	31	0	0	5
उत्तराखंड	57	2	0	15	0	0	0	0	0
झारखंड	5	14	8	4	14	8	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	0	0	0	136	136	23	5	11	0
मेघालय	-	-	5	-	-	1	-	-	0
हिमाचल प्रदेश	-	-	0	-	-	12	-	-	0
उत्तर प्रदेश	-	-	1	-	-	-	-	-	0

@ : 5 अगस्त 2013 तक

**सारणी VII.8: राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश@**

(₹ बिलियन)

माह	एटीबी में निवेश			आईटीबी में निवेश			कुल		
	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	108.6	231.6	317.40	864.1	863.1	1002.31	972.7	1094.7	1319.71
मई	145.3	327.6	378.40	728.1	768.2	913.99	873.4	1095.8	1292.39
जून	249.8	415.9	549.03	677.9	681.6	729.45	927.7	1097.5	1278.48
जुलाई	326.4	440.6	672.28	613.9	654.9	609.91	940.3	1095.5	1282.19
अगस्त	329.6	450.3	721.82	645.2	756.3	646.58	974.8	1206.6	1368.40
सितंबर	327.6	505.5		615.4	707.9		943.0	1213.4	
अक्तूबर	297.2	521.9		613.7	748.8		910.9	1270.7	
नवंबर	267.9	496.1		667.1	844.0		935.0	1340.1	
दिसंबर	240.2	523.8		762.0	875.7		1002.2	1399.5	
जनवरी	326.3	546.6		717.1	912.2		1043.4	1458.8	
फरवरी	381.7	498.9		774.5	1088.8		1156.2	1587.7	
मार्च	329.5	337.2		986.5	1295.5		1316.0	1632.7	
औसत	276.5	441.0		722.1	848.9		998.6	1289.9	

@ : 5 अगस्त 2013 तक

में बकाया निवेश की राशि मार्च 2012 की समाप्ति के 966 बिलियन रुपये से बढ़कर मार्च 2013 की समाप्ति पर 1,181 बिलियन रुपये हो गयी। नीलामी खजाना बिलों में राज्य सरकारों का साप्ताहिक औसत निवेश पिछले वर्ष के 277 बिलियन रुपये से बढ़कर 441 बिलियन रुपये हो गया। मार्च 2013 की समाप्ति पर नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में बकाया निवेश मार्च 2012 की समाप्ति के 220 बिलियन रुपये की तुलना में अधिक अर्थात् 286 बिलियन रुपये रहा।

VII.14 रिजर्व बैंक राज्य सरकारों की ओर से समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ) का रखरखाव करता है जो बाजार से ली गई उधारियां/देयताओं के परिशोधन के लिए कुशन प्रदान करता है। साथ ही रिजर्व बैंक गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) का भी रखरखाव करता है जिसका उपयोग राज्य स्तरीय उद्यमों अथवा अन्य निकायों द्वारा उधार के संबंध में जारी गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं की चुकौती के लिए किया जाता है (31 मार्च

2013 तक 21 राज्य सरकारों ने सीएसएफ में तथा 11 राज्यों ने जीआरएफ में अभिदान दिया)। मार्च 2013 की समाप्ति पर सीएसएफ और जीआरएफ के तहत बकाया निवेश राशि क्रमशः 485 बिलियन रुपये और 44 बिलियन रुपये थी।

VII.15 बैंकों द्वारा नियत ब्याज दर वाले दीर्घावधि के अधिक ऋण उत्पाद शुरू करने की संभाव्यता का मूल्यांकन करने वाली समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: श्री के.के.वोहरा) 22 जनवरी 2013 को रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाली गई। समिति की प्रमुख सिफारिशों में ये शामिल हैं: बैंकों द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में उनकी एकपोजर सीमा तक दीर्घावधि बांड (न्यूनतम परिपक्वता 5 वर्ष) का निर्गम, 5 वर्ष से अधिक अवधि वाली मीयादी जमा योजनाओं को लोकप्रिय बनाना क्योंकि ये कर रियायत के लिए पात्र होती हैं, और बैंकों द्वारा नियत दर वाले दीर्घावधि (उदाहरण के लिए 30 वर्ष तक के) ऋण जारी करना जो उधारकर्ता की ईएमआई को कम करने में मदद करेगा।